



# विदेशों में क्यों धन जमा करते हैं भारतीय, इसकी वजह और शेल कंपनियों का सब

हाल में खबर आई है कि स्विस बैंकों में भारतीयों के जमा धन में भारी इजाफा हुआ है। वर्ष 2021 में भारत के लोगों और संस्थाओं की स्विस बैंकों में कूल जमा राशि 30,500 करोड़ रुपये थी। यह 14 साल के उच्च स्तर पर है।

स्विस बैंकों ने यह जो जानकारी दी है, वह वैध धन है, काला धन नहीं। विदेशों में या स्विस बैंक में भारतीयों का किनारा काला धन जमा है, इसका पता लगाना टटी खीर है।

अपने देश से जिस माथम से काला धन विदेशों में जाता है, उसे हम स्विसरिंग कहते हैं। स्विसरिंग में लोग से काला धन हवाला, आयात या निर्वाचन में अंदर इनवेस्टिमेंट तथा ऑवर इनवेस्टिमेंट के जरिए किसी टैक्स हेवन देश में कंपनी में डाल देते हैं, फिर वहाँ उस शेल कंपनी को बंद करके किसी दूसरे टैक्स हेवन देश में नई शेल कंपनी बनाकर उसमें पैसा लगा देते हैं।

इस तरह से छह चरणों में पैसे निकालते होए अंत में स्विट्जरलैंड भेजते हैं। ऐसे में छह स्तर होने पर छह शेल कंपनियां बनती हैं जो बंद होती हैं, जिसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। सरकार अगर चाहे भी तो एक स्तर स्तर तक ही पता लगा पाती है, उससे अगे पता नहीं लगा पाता है। लेयरिंग की इस प्रक्रिया में जहाँ से आखिरी बार स्विट्जरलैंड में पैसा जाता है, स्विट्जरलैंड



स्विस बैंक

देश में जितना काला धन पैदा होता है, उसका दस प्रतिशत बाहर जाता है, बाकी 90 प्रतिशत काला धन देश में ही रहता है। इसलिए अगर हमें काले धन पर अंकुश लगाना है, तो देश में ही उस पर लगाम लगाना चाहिए। अगर बाहर भेजे गए काले धन को पकड़ा गाहें, तो उसमें फिलता ही मिलेगी, क्योंकि सरकार को भी ठीक-ठीक पता नहीं कि किनना काला धन बाहर गया है और उसे कहाँ रखा गया है।

उतना दबाव नहीं होता कि वैध धन को विदेशों से देश में लाया जाए।

अगर यह काला धन नहीं है, तो फिर भारत के लोग स्विस बैंकों में पैसा कर्मी जमा करते हैं? इसकी कहाँ वजह है। जब भी अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता की स्थिति पैदा होती है, तो लोग अपने धन को जावरिसाफ़ (अलग-अलग जगह) बांधते हैं, इसके उक्ता जोखिम कम हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि इस बात का खतरा है कि रुपया गिरेंगे, तो वे अपना धन कर्फून एकसंघें में जमा कर देंगे। जो नियांतक है, वे अपना पैसा देश से लायें, जब अर्थव्यवस्था में विस्थिता आएगी और रुपये के गिरने का खतरा कम हो जाएगा।

और जो आयात करने वाले हैं, वे अपना पैसा इसलिए विदेशी बैंकों में जमा रखते हैं, क्योंकि सरकार को भी ठीक-ठीक पता नहीं कि किनना काला धन बाहर गया है।

अन्यथा रुपये का मूल्य गिरने पर उन्हें भारी बाटा होगा। इस तरह से

आयातक और नियांतक यह अनुमत लगाकर कि रुपया कमज़ोर होने पर भारी बाटा हो सकता है, अनन्य वैध पैसा विदेशी बैंकों में जमा करते हैं। इसके अलावा रिज़व बैंक की लिवरलाइन्ड रेमिंगेस स्कीम (एसआरएस) है, जिसके द्वारा जाहीर होने वाले डालर कोइ भी हर साल ढाई लाख डालर देश के बाहर ले जा सकते हैं। उसके चलते भी बहुत से लोग अपना धन कर्फून एकसंघें में जमा करते हैं। स्विस बैंकों में भारी बाटा होने के माध्यम से स्विस बैंकों में जमा कर देंगे। जो नियांतक है, वे अपना पैसा देश से लायें, जब अर्थव्यवस्था में विस्थिता आएगी और रुपये के गिरने का खतरा कम हो जाएगा।

और जो आयात करने वाले हैं, वे अपना पैसा इसलिए विदेशी बैंकों में जमा रखते हैं, क्योंकि सरकार को भी ठीक-ठीक पता नहीं कि किनना काला धन बाहर गया है।

अन्यथा रुपये का मूल्य गिरने पर उन्हें भारी बाटा होगा। इस तरह से इंडिविजुअल्स देश छोड़कर विदेश

अरुण कुमार

## संपादकीय

### वीडियो गेम्स की लत

वीडियो गेम खेलना धीरे-धीरे लत बन जाता है। उसके बाद संबंधित बच्चा खेले के बारे में नहीं सोचना चाहे, तब भी वह अपने-अपने भोके रोकने में सक्षम नहीं होता। हिंसा से भरपूर वीडियो गेम्स खेलने वाले लोग निषुम्ब हो जाते हैं।

हाल की दो घटनाओं ने आम जनास को झकझोर रखा है। इन दोनों का संबंध मोबाइल गेम्स की बड़ती लत से है। इनमें से एक घटना में 16 साल के एक लड़के पर अपनी ही मां की हत्या का आरोप लगा। बताया जाता है कि मां बेटे को मोबाइल गेम खेलने से मना करती थी। उधर दूसरी घटना में इसी बजह से बेटे ने खुदकुही कर ली। इन घटनाओं को मोबाइल्स गेम्स की कारण परिचय में खड़ी समस्याओं से दुनिया भर के मध्यवर्तीय परिवार जूँझ रहे हैं। ऐसी मुश्किलों से दुनिया भर के मध्यवर्तीय परिवार जूँझ रहे हैं। इनमें से एक घटना में 16 साल के एक लड़के पर अपनी ही मां की हत्या का आरोप लगा। बताया जाता है कि मां बेटे को मोबाइल गेम खेलने से मना करती थी। उधर दूसरी घटना में इसी बजह से बेटे ने खुदकुही कर ली। इन घटनाओं को मोबाइल्स गेम्स की डार्क फ़ार अपने-अपने भोके रोकने में सक्षम नहीं होता। कुछ दूसरे जनकारों का भी कहाना है कि हिंसा से भरपूर वीडियो गेम्स खेलने वाले लोग निषुम्ब हो जाते हैं। उन्हें हिंसक चिरंदेख कर कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग ताना से मुक्ति पाने के लिए वीडियो गेम का सहाया लेते हैं और अपराध करने की जगह अपना गुस्सा अॉनलाइन या वीडियो गेम पर उतारने लगते हैं।

### आम आदमी की आजीविका से अर्थव्यवस्था तक डिजिटल माध्यम से पहुंच बनाने की कोशिश

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं, किसानों और उद्यमियों को कर्ज की सरल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 13 सरकारी योजनाओं से जुड़े क्रिडिट लिवर्ड पोर्टल जन समर्थ की शुरुआत की है। उन्होंने इस मोर्के पर कर्ज की शुरुआत की है। उन्होंने इस मोर्के पर कर्ज की शुरुआत की है। उन्होंने इस मोर्के पर कर्ज की शुरुआत की है।

यह काजा जा रहा है कि भारत में करोड़ों गरीबों द्वारा एवं कर्मचारियों के बीच अर्थव्यवस्था के औपचारिक माध्यम में शामिल करके उन्हें डिजिटल माध्यम के जरिये यारदारी दिये जाएं और भवित्व और बैंकिंग सेवाओं की सरल उपलब्धता सुनिश्चित किए जाएं। आम आदमी तक सभियों की डिजिटल बुनियादी ढांचा कर्फून कर देने से आम आदमी को आसान बनाने में अहम भूमिका निभाएगा, वहीं युवाओं के लिए मनवाही कृपनी व उद्यम खोलने और यता पाने के काम को आसान बनाएगा।



आमजन और वित्तीय समावेशन

देश में डिजिटल बुनियादी ढांचा कर्फून है। डिजिटल लेन-देन की बुनियादी जरूरत-कॉयटर और इंटरनेट बड़ी संख्या में लोगों की पहुंच से दूर है। वित्तीय लेन-देन के लिए बड़ी संख्या में लोग डिजिटल भूगतान तकनीकों से अपरिचित हैं। छोटे गांवों में बिजली की पर्याप्ति पहुंच नहीं है। साथ ही मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भी देश अभी बहुत पीछे है।

दुनिया भर में यह भी रेखांकित हो रहा है कि भारत में आम आदमी और छोटे लोगों को पहुंच से दूर है। वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में आम आदमी तक सभियों की खातों की खातों में जमा रखने की वित्तीय समावेशन का लाभ लेने के लिए आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वित्तीय समावेशन का डायर पर कई बातों और चुनौतियों भी दिखाई दे रही हैं।

जानूर को प्रकाशित माइक्रोफाइंस इंस्ट्रीट्यूशंस नेटवर्क (एमएफआईएस) के नए अंकड़ों के मुताबिक, जॉलीपी 31 मार्च, 2022 तक 10 प्रतिशत बढ़कर 2,85,441 करोड़ रुपये हो गया, जो 31 मार्च, 2021 तक 2,59,377 करोड़ रुपये था।

खास बात यह भी है कि स्क्रम वित्त उद्योग से बड़ी संख्या में लोग लाभांशित हो रहे हैं। इसके तहत मार्च, 2022 में ज्ञा खाते बढ़कर 11.31 करोड़ हो गए, जो मार्च, 2021 में 10.83 करोड़ थे। इसमें कोई दो मात्र नहीं हो रहा है कि जनधन योजना (पीएमजेवीडीए) ने देश में वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में आम आदमी तक सभियों की खातों की खातों में जमा रखने की वित्तीय समावेशन का लाभ लेने के लिए आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वित्तीय समावेशन का डायर पर कई बातों और चुनौतियों भी दिखाई दे रही हैं।

जयंतीलाल भंडारी

## अफगानिस्तान में भीषण भूकंप से 1000 लोगों की मौत

### 600 घायल, पाकिस्तान में भी बर्बादी



अफगानिस्तान की न्यूज़ एंजेंसी बख्तार ने इस भूकंप से अत्यधिक घायल हो गए हैं। इसमें ज्यादा ग्रामीण वायाकी और खोस इलाके हुए हैं। यहाँ कई गांव खंडहर में बदल गए हैं। पाकिस्तान में भी अफगानिस्तान से सटे कई इलाकों में बड़ी ही अपरिक्रमित किपिंग की विदेशी जिपारोंके लिए एक रूपरेखा है। इसमें भीषण भूकंप आया है। इसमें सं

## सीएम के सलाहकार ने की नियमा, गरवा, घुटवा अंड बाड़ी योजना की समीक्षा

गौठन का किया अवलोकन, समूह की महिलाओं से की बातचीत

जोहार छत्तीसगढ़-  
महासमुद्र।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सलाहकार प्रदीप शर्मा ने सिरपुर भ्रमण एवं झलप गौठन का अवलोकन किया। समूह महिलाओं से बातचीत की उनकी निर्मित सामग्री देखी और सारहना की।

इसमें पहले उन्होंने कलेक्टरों रेट कायालय के सभाकक्ष में शामन की प्लैनिंग व्योजना नरवा गरवा घुटवा अंड बाड़ी के कियाहिंग को समीक्षा की। शर्मा ने गोबर खरीदी एवं चर्मी खाद निर्माण की भी समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि गोबर खरीदी नियमित होती रहे। गोबर खरीदी की विभागीय उनका इलाज भी किया जाए। उन्होंने पशुपालकों के कम पंजीयन पर चिन्ता जाहिर की। पशु विकासी अधिकारी को 15 दिवस



के भीतर पशुपालकों का प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा ग्राम गौठन समिति को नियमित करें और उन्हें प्रशिक्षण दें। सलाहकार प्रदीप शर्मा ने कहा कि गौठन से जुड़े काम और बेहतर होने से करें। महासमुद्र एक समृद्ध क्षेत्र है लिहाजा इसका लाभ भी योजनाओं और उनसे जुड़े हितहारियों को हासिल हो। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं गौठन से जुड़ी हैं। वह सब्जी-भाजी लगाएं। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाए। बघिया को देखते हुए गौठन में मवेशियों के व्योजना और उनका इलाज भी किया जाए। उन्होंने कहा कि गौठनों को रुल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित करने के लिए वहां और

अवगत कराया। साथ ही आगामी योजना के बारे में बताया। सीईओ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में हो रही है।

उन्होंने बताया कि समय-समय पर गोधन और एनजीओ की कियाहिंग व्यापार से संबंधित विभिन्न जाता है और योजनाओं को लागू करने में आ रही दिक्कतों की जाती है। इसके अधिकारियों के संबंधित अधिकारी को बीच इन योजनाओं को और एसडीएम भागवत जायसवाल सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी को बीच एसडीएम भागवत जायसवाल सहित व्यापारी एवं जिले के संबंधित अधिकारी को बीच एसडीएम भागवत जायसवाल सहित व्यापारी सीईओ नियमित ब्लॉक है इस पर भी विचार किया जाता है। उन्होंने किसानों और ग्रामीणों की ओर लाभ भी देखा। उन्होंने कहा कि इससे पशुपालकों का लाभ भी होगा। उन्होंने कहा कि गौठनों को रुल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित करने के लिए वहां और

अधिक आर्थिक गतिविधियां

संचालित करने की आवश्यकता है।

इससे ग्रामीण स्वावलंबन की

राह में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने

अधिकारियों को गौठनों में विभिन्न

आर्थिक गतिविधियों के संचालन में नियरतरता लाना के

क्रियान्वयन में नियरतरता लाना के

निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह सरकार की संसद में सहायता समूहों को गौठनों में एक है। ग्रामीण

अवगत करने का आहान किया है। उन्होंने कहा कि इससे खोरोंकों की ओर गोधन

संवर्धन योजना से होने वाला लाभ

भी देखा जाए। उनका स्वावलंबन किया

जायसवाल की ओर सहायता लाना भी देखा जाए। उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। उन्होंने स्व

सहायता समूह की मिलिंगल और

सांचालित विभिन्न प्रकार की

सीधी व्यापारियों के साथ अधिकारी

